

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ : मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन

डॉ० अंजू कुमारी

व्याख्याता, ग्रामीण अर्थशास्त्र, पंडित तारणी झा कॉलेज, बाँका

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 15 September 2020

Keywords

ग्रामीण, रोजगार, समस्याएँ, बेरोजगारी

ABSTRACT

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम “नींव की ईंट” की तरह है जो स्वतः दिखाई न पड़ने के बावजूद महल के निर्माण में आधारभूत तत्व का काम करता है। वर्ष-2010 में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते वक्त विश्व ने भारत को एक ‘महाशक्ति’ के रूप में देखा है।

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएँ सबसे अधिक व्यापक हैं, भयावह हैं और सबसे अधिक गहन भी। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि यह “खुली बेरोजगारी” के रूप में प्रगट नहीं होती। इसका स्वरूप प्रच्छन्न होता है; यह अल्प-रोजगार के रूप में स्पष्ट होता है और इसकी प्रकृति “छिपी हुई बेरोजगारी” की होती है।

भूमिका :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम “नींव की ईंट” की तरह है जो स्वतः दिखाई न पड़ने के बावजूद महल के निर्माण में आधारभूत तत्व का काम करता है। वर्ष-2010 में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते वक्त विश्व ने भारत को एक ‘महाशक्ति’ के रूप में देखा है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी विशेषज्ञों की भारी-भरकम समृद्ध युवा-वर्ग, अशांत पड़ोसियों से घिरा शांतप्रिय देश, स्थिर आदर्श लोकतान्त्रिक सरकार और इस जैसे-अनेक सार्थक-कारक हमारे गणतंत्र के शुक्लपक्ष में चार चाँद लगा रहे हैं।

दुनियाँ बूढ़ी हो रही है और भारत जवान। हमारी दो तिहाई आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनियाँ के आने वाले वक्त में यह युवा आबादी और बढ़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय भारत का होगा। यही वजह है कि हमारी सरकार, हमारा व्यापार-तंत्र और हमारे योजनाकार लगातार सोच रहें हैं कि कैसे इतनी बड़ी आबादी को राष्ट्र-निर्माण के काम में लगाएँ ?

आँकड़े बताते हैं कि भारत के 47.00 प्रतिशत लोगों की उम्र बीस साल से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2015 तक यह 55.00 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। दुनियाँ में भारत को आज आर्थिक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका महत्वपूर्ण पक्ष युवा-शक्ति और युवा वर्ग है। वर्ष-2005 में युवाओं की (15-24 वर्ष) की आबादी चीन में-22 करोड़, भारत में-21 करोड़, अमेरिका में-4 करोड़, पाकिस्तान में-3 करोड़ तथा रूस में-25 करोड़ था। वर्ष-2020 के लगभग भारत में औसत उम्र 29 वर्ष, चीन में 37 वर्ष, अमेरिका में 37 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होने के अनुमान हैं यानी दस साल बाद भारत में युवाओं का ही बोल-बाला होगा। कल-तक बेरोजगारी समस्या बनी हुई थी मनुष्य के लिए, जनसंख्या के लिए, लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई हैं।

इक्कीसवीं सदी में मनुष्य समस्या है, जनसंख्या समस्या है—बेरोजगारी के लिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : यह कार्यक्रम अक्टूबर-1980 में प्रारम्भ किया गया था। पूर्व में संचालित “काम के बदले अनाज कार्यक्रम” को पुनर्गठित करके इसका नाम “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम” रखा गया। 01 अप्रैल, 1989 से इस कार्यक्रम को “जवाहर रोजगार योजना” में सन्निहित कर दिया गया। पुनः इसे “जवाहर ग्राम समृद्धि योजना” के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 1999 में शामिल किया गया। तत्पश्चात यह कार्यक्रम “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम” (नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष-2010 में “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम” (मनरेगा) के नाम से संचालित है।

रोजगार प्राप्त करने की समस्या आज विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी की समस्या के आलोक में दो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण अतिआवश्यक है—पहली, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की अवधारणा का तथा दूसरी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का। इस संदर्भ में पहली बात यह है कि ये अवधारणाएँ स्थैतिक नहीं होतीं, बल्कि ये गत्यात्मक होती हैं। दूसरी बात यह है कि हर युग में बेरोजगारी की समस्याएँ उस विशिष्ट-युग की “शिशु” होती हैं।

बेरोजगारी : जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे, ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अर्थात् बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है परन्तु प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम करने का अवसर नहीं मिलता है।

आर्थिक चिन्तन के इतिहास में बेरोजगारी के अवधारणा की विवेचन के कई सोपान रहे हैं, जहाँ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने “बेरोजगारी” की अवधारणाओं को अपने सिद्धान्तों से पूर्ण बहिष्कृत कर पूर्ण रोजगार की सामान्य दशा को मान्यता दी, वहीं कीन्स ने प्रथम बार, तीसा की महान् मंदी के सन्दर्भ में, अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “जेनरल थ्योरी” में न्यून-रोजगार संतुलन का विवेचन किया। “कीन्स” का सर्वाधिक प्रमुख अवदान यह रहा है कि इन्होंने समाज के आर्थिक चिन्तन एवं आर्थिक सिद्धान्त को “पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता” के कटघरे से निकालकर इसे “बेरोजगारी एवं अल्प-बेरोजगारी” की ठोस तथा वास्तविक धरातल की मान्यता पर आधारित कर स्थापित किया।

लेकिन “कीन्स” का बेरोजगारी के सन्दर्भ में विवेचन विकासशील देशों के सन्दर्भ में न तो प्रासंगिक है और न ही उपयोगी। भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की बहुलता होती है एवं कृषि ही इनका मुख्य-आधारगत पेशा। चक्रिय बेरोजगारी की समस्या इन देशों के लिए प्रमुख समस्या नहीं होती है। अतः कीन्सीयन विश्लेषण के यंत्रों द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी तथा इसकी प्रकृति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ग्रामीण समाज में इसके विश्लेषण के लिए यह अनिवार्य है कि हम निर्धनता एवं बेरोजगारी को “सगी बहनों” की तरह मानें और इसके निराकरण के लिए नितांत भिन्न नीति-यंत्रों को प्रयोग में लाएँ।

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएँ सबसे अधिक व्यापक है, भयावह है और सबसे अधिक गहन भी। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि यह “खुली बेरोजगारी” के रूप में प्रगट नहीं होती। इसका स्वरूप प्रच्छन्न होता है; यह अल्प-रोजगार के रूप में स्पष्ट होता है और इसकी प्रकृति “छिपी हुई बेरोजगारी” की होती है।

भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है; विशेष कर ग्रामीण समाज में जहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहाँ बेरोजगारी का रूप अतिभयावह है। ग्रामीण बेरोजगारी ने ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण समाज में बेरोजगारी की समस्या एक अभिशाप है; इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण समाज में बेरोजगारी का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है; क्योंकि इससे आर्थिक विकास की गति अति मंद पड़ जाती है, वहीं दूसरी ओर यदि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तो अर्थ-व्यवस्था में व्यापक सुधार होता है। इस तरह बेरोजगारी की वृद्धि से देश का सामाजिक-आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है तथा समाज में असन्तोश, बेकारी और पलायन की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है।

बेरोजगारी का स्वरूप : इक्कीसवीं सदी के भारत में बेरोजगारी का अलग-अलग स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे बेरोजगारी के प्रकार या वर्गीकरण भी कह सकते हैं; जो वर्तमान समय में निम्न रूपों में पायी जाती हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी : जब देश में पूँजी के साधन सीमित होते हैं तो काम चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है तो ऐसे में बहुत-से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इस तरह के बेरोजगारी को ही “संरचनात्मक

बेरोजगारी” कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का यही स्वरूप ज्यादा देखने को मिलता है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी : किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होते हैं, तो उसे “प्रच्छन्न बेरोजगारी” कहा जाता है। बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, जैसे-ग्रामीण भारत के अन्तर्गत कृषि-कार्य में इस तरह की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। प्रो० नर्से के अनुसार-“अल्पविकसित देशों में कृषि-क्षेत्र में कार्यरत बहुत से खेतीहर मजदूर ऐसे होते हैं, जिन्हें यदि हटा दिया जाए तो न कृषि-कार्य बाधित होगा और न ही कृषि उत्पादन में कोई कमी होगी अर्थात् कृषि उत्पादन में इनका योगदान शून्य के बराबर रहता है। ऐसे खेतीहर मजदूर आर्थिक दृष्टि से बेकार कहलाएँगे, क्योंकि वे उत्पादन कार्य में नहीं लगे हुए हैं। इसलिए उन्हें बेरोजगार कहना अधिक उपयुक्त होगा। चूँकि देखने में ये श्रमिक कार्य में लगे होते हैं, इसलिए इनकी बेरोजगारी छिपी रहती है।” ऐसे बेरोजगारों का वास्तविक अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन इस बात से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और यह भी कि यदि ऐसे लोगों को कृषि-कार्य से निकाल दिया जाय, तो सम्भवतः कृषि-उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी। इतना ही नहीं इससे शेष लोगों में काम की सक्रियता बढ़ेगी।

ए० के० सेन का मत है कि “प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति कार्यकारी घण्टों की कम संख्या का रूप धारण कर लेती है।” ऐसे ग्रामीण व्यक्ति ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं।

खुली बेरोजगारी : खुली बेरोजगारी के अन्तर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के ही बेकार रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा-बहुत भी काम नहीं मिलता है। भारत में बहुत से श्रमिक गाँवों से शहरों की ओर काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किन्तु काम उपलब्ध न होने के वहाँ वे बेरोजगार पड़े रहते हैं।

शोध-क्षेत्र, अध्ययन पद्धति एवं प्रतिदर्श के सन्दर्भ में भारत के भौगोलिक मानचित्र के अन्तर्गत बिहार राज्य की प्रशासनिक ढाँचा को रेखांकित कर, वर्तमान शेष बिहार के परिदृश्य में मुंगेर जिला के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में खडगपुर प्रखण्ड के गाँवों की सीमारेखा एवं भौगोलिक परिदृश्य को अध्ययन-क्षेत्र के रूप में उकेरा गया है।

शोध-अध्ययन हेतु अपनायी गयी अध्ययन पद्धति के सन्दर्भ में प्रासंगिक, उपयोगी तथ्यों एवं आँकड़ों के संग्रहीकरण का तरीका सुनिश्चित कर, आँकड़ों के यथोचित सुनियोजन एवं इनके समुचित विवेचन-विश्लेषण के आधार पर महत्वपूर्ण, वास्तविक एवं उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर नियोजित किया गया है।

हर देश का इतिहास उत्थान-पतन की घटनाओं से परिपूर्ण होता है। जो आज धूल-धूसरित है वही, कल पुष्प से सुवासित होगा। भारत के अतीत का समय-चक्र परिवर्तनशील रहा है। कभी सोने की चिड़ियाँ कहलाने वाले इस देश को विदेशी आततायियों ने लूटा-खसोटा, बाद में अंग्रेजों ने लगभग 250 सालों तक इस देश के प्राकृतिक संपदा का दोहन किया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है; आज फिर वही भारत अपने बलबूते पर विश्व की अगुआई करने को तैयार है।

हमारा देश 15 अगस्त 1947 ई0 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र के साथ-साथ एक विकासशील देश है। 26 मार्च 2001 को भारतीय जनगणना के अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या-1,02,70,15,247 रही; जिनमें पुरुषों की जनसंख्या - 53,12,77,078 तथा महिलाओं की जनसंख्या - 49,57,38,169 है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 है। देश में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 35 है; जिसमें बिहार राज्य भारत के पूरब में मध्य-क्षेत्र के अन्तर्गत है।

बिहार : भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में गंगा के मध्य बेसिन में $20^{\circ}20'10''$ उत्तरी अक्षांश से $27^{\circ}31'15''$ उत्तरी अक्षांश के मध्य और $83^{\circ}19'50''$ पूर्वी देशांतर से $88^{\circ}17'40''$ पूर्वी देशांतर तक भारत संघ के बिहार राज्य का विस्तार पटल है। उत्तर से दक्षिण तक इस राज्य की लम्बाई 362 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94.143 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का ग्यारहवाँ राज्य है। 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार को देश में तीसरा स्थान प्राप्त है।

बिहार राज्य के पूरब में झारखण्ड एवं बंगाल, पश्चिम में उत्तरप्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड और उत्तर में नेपाल की सीमा रेखा है। भौगोलिक बनावट की दृष्टि से बिहार को दो भागों में बाँटा गया है— उत्तर में गंगा का समतल मैदान तथा दक्षिण का पठारी मैदान। इन दोनों भाग का अपना विशिष्ट महत्व है।

बिहार शब्द “विहार” का तद्भव है जिसका अर्थ है “मठ”। यहाँ तीन प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं — भोजपुर, मिथिला और मगध का सांस्कृतिक क्षेत्र। बिहार का इतिहास प्राचीनकाल से ही अत्यन्त गौरवपूर्ण है। बिहार को बौद्धिक ज्ञान एवं विभिन्न संस्कृतियों से समायोजन करने की क्षमता रखने वाला अग्रदूत राज्य माना गया है। बिहार में आर्यों की संस्कृति का विस्तार 1000 ई0 पूर्व से 800 ई0 पूर्व के मध्य में प्रारम्भ हुआ। प्राचीन काल से ही बिहार सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक जागृति का केन्द्रबिन्दु है। मगध के महान् सम्राट अशोक एक शक्तिशाली राजा थे। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी बनवायी, जिसका नाम “पाटलिग्राम” रखा था।

अथर्ववेद में मगध प्रदेश का उल्लेख मिलता है। वर्तमान आधुनिक पटना नगर की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह ने पाटलिपुत्र नगर में ही किया था। विश्व के महान् राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ “चाणक्य” की मदद से चन्द्रगुप्त मौर्य सिंहासनारूढ़ हुए थे। मुगलकाल में बिहार के वीर पेशवाह ने हुमायूँ को पराजित कर बिहार से बाहर भगा दिया था। सिक्खों के महान् “धर्म गुरु” गुरु गोविन्द सिंह का जन्म बिहार के पटना सिटी में हुआ था। गौतम बुद्ध तथा महावीर को “ज्ञानोदीप्ति” बिहार की मिट्टी से ही प्राप्त हुई। सन् 1764 ई0 में बक्सर-युद्ध के बाद बिहार पर ब्रिटिशशासन का प्रभुत्व स्थापित हो गया।

स्वतंत्रता पश्चात् राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बिहार की सीमा में एक बार फिर परिवर्तन हुआ।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों के अंतरण) अधिनियम, 1956 के फलस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को बिहार की कुल 3,166 वर्गमील भूमि तथा 14,46,385 लोगों की आबादी बंगाल को अंतरित कर दी गयी। फलस्वरूप बिहार-विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या-331 से घट कर 318 हो गयी। 1977 में जनसंख्या वृद्धि अनुपात के आधार पर बिहार विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 318 से बढ़ाकर 324 की गयी। तत्पश्चात् 15 नवंबर 2000 में एक बार पुनः बिहार राज्य का बंटवारा हुआ। उसके आवान्तर, बिहार से 18 जिलों को अलगकर एक नवसृजित राज्य ‘झारखंड’ बना। सम्प्रति अब बिहार केवल 38 जिलों का ही राज्य है।

बिहार मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। बिहार प्राकृतिक सम्पदा एवं कृषि के क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य है। बिहार की भूमि समतल एवं अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ जोतों का आकार छोटा एवं अत्यधिक अपखंडित है। वस्तुतः राज्य का आर्थिक विकास कृषि के विकास पर ही अधिक निर्भर है। राज्य में कृषि हेतु सिंचाई के लिए जल के प्राकृतिक स्रोत के अलावे नहर, बाँध, तालाब, कुआँ, पम्पिंगसेट आदि भी हैं, लेकिन, जल कम मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ उचित प्रबंधन एवं संकलन के अभाव में सिंचाई हेतु जल एवं कृषिजन्य आधुनिक साधनों की सर्वत्र कमी है। कृषि की आर्थिक संभाव्यता का निर्णय अंततः उसके सुनिश्चितिकरण और लाभकारी अवसरों के उपयोग पर ही निर्भर है। बिहार के कृषि-कार्यों में कुल 76.0 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न हैं। कृषि-कार्य के लिए कृषि मजदूरों का महत्व उतना ही अनिवार्य है जितना कि मानव-शरीर के लिए रक्त का।

बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल-94143 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष-2001 की जनगणना के अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या-8,29,98,509 है; जिनमें 4,32,43,795 पुरुष हैं तथा 3,97,54,714 महिलाएँ हैं। जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या-1,30,48,608 तथा जनजातियों की संख्या-7,58,351 है। बिहार के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या-7,4,3,16,709 तथा शहरी जनसंख्या 86,81,800 है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 86.83 तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 13.17 है। भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत 10.23 है। यहाँ पुरुष-महिला का अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 921 महिला का है। जन्म दर 31.9 प्रतिशत है; जबकि यहाँ मृत्यु दर 08.8 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य के निवासियों की साक्षरता दर कुल-47.53 प्रतिशत है; जिनमें 60.32 प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता दर है; जबकि 33.57 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता दर है। साक्षरता दर का उच्चतम औसत 63.82 प्रतिशत पटना का है; जबकि साक्षरता दर का न्यूनतम औसत 31.02 प्रतिशत किशनगंज का है। पूरे वर्ष में यहाँ औसत वर्षा 1205 मिलीमीटर होती है। पूरे वर्ष में यहाँ वर्षा की औसत दिनों की संख्या 52.5 प्रतिशत है।

बिहार का प्रमुख पशु मेला सोनपुर का है। इसके बाद दूसरा पशुमेला भोजपुर जिला के “बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ” की नगरी “ब्रह्मपुर धाम” में लगता है। सन्-1934 ई0 में बिहार का पहला भूकम्प मुंगेर में हुआ था। बिहार में पटना का “गंगा सेतु” विश्व में सबसे बड़ा सड़क पुल है। बिहार में हवाई-अड्डा-पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया और भागलपुर

में है। यहाँ प्रमुख जल-परिवहन सेवा सुल्तानगंज घाट, मुंगेर एवं मोकामा में है।

मुंगेर : हर युग, हर काल में मुंगेर की भूमि ने वक्त की रेत पर कुछ ऐसे निशान उकेरे हैं, जो अमिट बन गये। सच तो यह है कि मुंगेर का अतीत इतना समृद्ध रहा है कि वर्तमान उसी में डूबा नजर आता है। वेद-पुराणों में वर्णित मुंगेर का अपना इतिहास गौरवमयी है। कल-कल निनादित, पतितपावनी, पुण्यसलिला, उत्तरवाहिनी माँ भगीरथी के पावन-तट पर अवस्थित मुंगेर सैकड़ों-हजारों वर्षों के इतिहास में गुलाब की तरह खिलता रहा है। वास्तव में, यह नगर हमारे ऐतिहासिककाल का धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत का एक नायाब नमूना है।

मुंगेर का इतिहास वर्षों पुराना है। कभी यह मुद्गल ऋषि की तपोभूमि और प्रवचन-स्थल रहा, तो कभी भगवान् राम का विश्राम-स्थल। कभी माता सीता की उपासना स्थल रहा और कभी अग्नि-परीक्षा स्थल, कभी भगवान बुद्ध का पर्यटन स्थल, तो कभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का विहार स्थल, तो कभी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य का गढ़ तथा कभी

भीम का अज्ञातवास का गवाह स्थल भी रहा है। इसी मुंगेर में दीर्घतमा ऋषि ने ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना की थी। इतिहास साक्षी है राजवंशों और ऋषि-परम्पराओं की गरिमा और महिमा से मुंगेर सदा मंडित रहा है। पूर्व काल के एक महान सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी पसंद के अनुरूप विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा वास्तु-शास्त्र के आधार पर वर्तमान् मुंगेर नगर का निर्माण करवाया था।

निष्कर्ष :

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएँ सबसे अधिक व्यापक है, भयावह है और सबसे अधिक गहन भी। दुनियाँ बूढ़ी हो रही है और भारत जवान। हमारी दो तिहाई आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनियाँ के आने वाले वक्त में यह युवा आबादी और बढ़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय भारत का होगा। यही वजह है कि हमारी सरकार, हमारा व्यापार-तंत्र और हमारे योजनाकार लगातार सोच रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी आबादी को राष्ट्र-निर्माण के काम में लगाएँ ?

संदर्भ सूची :

- [1]. त्रिपाठी, रेणु (2017) : ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
- [2]. कुरुक्षेत्र मई, 2018
- [3]. कुरुक्षेत्र जून, 2017
- [4]. कुरुक्षेत्र जनवरी, 2004
- [5]. योजना फरवरी, 2018